DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली ।
मंगलवार, 9 जनवरी 2024
NAME OF NEWSPAPERS----------
दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2024
--DATED----------

बवाना : हेलीपैड रोड को KMP से जोड़ने की मांग

■ एनबीटी न्यूज, आउटर दिल्ली: बवाना की सड़कों पर ट्रैफिक का लोड बहुत अधिक बढ़ गया है। इसकी वजह से बवाना के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग जाम से परेशान है। इसे लेकर के रोहिणी सेक्टर 36 के हेलीपैड रोड को केएमपी (कुंडली-मानेसर एक्सप्रेस वे) तक जोड़ने की मांग तेज हो गई। लोगों ने अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जाम से छुटकारा दिलाने की मांग की है।

एनएचएआई, डीडीए समेत कई विभागों को ग्रामीणों ने भेजा प्रस्ताव

'आप और हम' संस्था ने यहां सड़क बनाने की मांग को लेकर डीडीए, नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित कई अन्य विभागों को अपना प्रपोजल भेजा है। संस्था के सचिव विशाल वत्स ने बताया कि आने वाले दिनों में बवाना के पास हरियाणा के खरखोदा गांव इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है। यहां आने वाली कमर्शल गाड़ियों के साथ ट्रैफिक का लोड गांव की संकरी सड़कें नहीं उठा पाती हैं। इसके कारण आए दिन यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। रिठाला रोहिणी हेलीपैड से एक नई सड़क को केएमपी तक बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कई गांव को जोड़ते हुए यहां के लोगों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता होगा।

दिल्ली के गांवों में 'अवैध गांव'

ग्राम सभा की जमीन पर ग्रामीणों ने किया मनमाना कब्जा

अजय राय • नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के गांवों में फैला अवैध कब्जे का जाल ग्रामोदय अभियान के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकती है। गांवों का हाल जानने के लिए पहुंचे अधिकारियों को सबसे अधिक ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा दिखा। स्थिति यह है कि गांवों में जिसको जहां मौका मिला वहीं सरकारी जमीन को अपना बनाने की कोशिश की। घर के आसपास की ज्यादातर जमीन कब्जा हो चुकी है। इससे संकरी गलियां, सीवर का पानी निकलने की समस्या विकराल बन गई है। वर्षों से गांवों की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी अब यह स्थिति देखकर चकरा रहे हैं।

गांवों की दशा सुधारने के लिए उपराज्यपाल ने हाल ही में ग्रामीणों संग संवाद कार्यक्रम किया और करीब 1,300 करोड़ के फंड से ग्रामोदय अभियान के तहत कायाकल्प करने की तैयारी है। इसी के अंतर्गत दिल्ली के 11 जिलों के जिलाधिकारी रविवार व सोमवार को अपने-अपने जिले के गांवों के दौरे पर निकले और जमीनी सच्चाई देखी।

निरीक्षण के दौरान हर गली नुक्कड़ पर अवैध कब्जे की स्थिति देखकर जिलाधिकारी चकरा गए। बात-बात में इलाके के पटवारी को तलब किया और पटवारी ने नक्शा दिखाकर कहीं काम चलाऊं तो कहीं कब्जा होने की स्थिति बताई। इस दौरान कब्जे के कारण संकरी सड़कें, सिमटते नाले और बंद गलियां दिखीं। इससे गांव की सड़कों पर जाम की स्थिति और ओवरफ्लो होते नाले दिखे। दरअसल, इतना ज्यादा अवैध कब्जा हो गया है कि आबादी के हिसाब से नालों को चौड़ा करने की जगह नहीं बची है।

वसंत विहार सबडिवीजन के समालखा गांव से ही इस स्थिति को समझा जा सकता है। रविवार को नई दिल्ली के जिलाधिकारी इस गांव में पहुंचे थे। यह गांव कापसहेड़ा के पास है। यहां एयरपोर्ट भी सामने है। इस गांव की जमीन पर तमाम फार्म हाउस व वेयर हाउस बने हैं।

सरकारी रिकार्ड के अनुसार गांव में 268 बीघा ग्राम सभा की जमीन है, लेकिन इतना ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है कि काफी कम जमीन बची है। कालोनियां काटी गई हैं। तमाम दुकानों के आगे पांच-पांच फुट हिस्सा दुकानदारों के कब्जे में हैं। करीब 50 हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग हर घर अपनी सुविधा से बने हैं। इसी गांव में सोनिया गांधी कैंप है। निरीक्षण के क्रम में ही यहां सड़क किनारे दो मंजिला मकान का निर्माण दिखा। सड़क और निर्माण की स्थिति को देखकर डीएम ने तुरंत निर्माण रोकने का आदेश दिया।

पटवारी से नक्शे में स्थिति समझते नई दिल्ली के डीएम संतोष कुमार राय (कोट में) • जागरण

डीएम ने कहा, समाधान के लिए त्रिस्तरीय कार्य योजना बनेगी

नई दिल्ली के डीएम संतोष कुमार राय ने कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए तीन स्तर की कार्ययोजना बनाई जाएगी। पहले चरण में नियमित झाड़ू लगाने व जलापूर्ति का समय ठीक करने जैसे आसानी से होने वाले कार्य को किया जाएगा। दूसरे चरण में छोटी अवधि वाले काम किए जाएंगे। इसके तहत डार्क स्पाट दूर करने और वोटर कार्ड अपग्रेड करने आदि होंगे। तीसरे चरण में सीमांकन का काम किया जाएगा। यह मामला कई विभागों से जुड़ा है और समय देने वाला है तो इस पर लंबी अवधि का प्लान बनाया जाएगा। डीएम ने बताया कि दिल्ली के गांव अब शहरीकृत हो चुके हैं। ऐसे में यहां की ग्राम सभा की सरकारी जमीन का मालिकाना हक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है। बैठक में डीडीए के अधिकारी नहीं पहुंचे थे, इसलिए निरीक्षण के दौरान स्थिति समझने में बाधा आई। अब उनके साथ बैठक कर सीमांकन के लिए कार्ययोजन बनाई जाएगी। सीमांकन करने के बाद नोटिस देकर अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वर्षों की अनदेखी से समस्या हुई विकराल

गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी वर्षों से आंख मूंदे रहे। जनप्रतिनिधियों ने भी वोट बैंक के चक्कर में इसे रोकने की बात न चौपाल में की और न विधानसभा में। कब्जा के साथ गांव की आबादी बढ़ती गई और मुलभूत ढांचा कम पड़ता चला गया। स्थिति यह है कि गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो एंबुलेंस दरवाजे पर नहीं जा सकती।

निराशाजनक स्थिति >> संपादकीय